

विकसित भारत 2047: एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की संभावनाएं

डा० अरविन्द कुमार शुक्ल¹

¹सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला स्ना० महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर उ०प्र०

Received: 15 Feb 2025, Accepted & Reviewed: 25 Feb 2025, Published: 28 Feb 2025

Abstract

भारत, जिसे प्राचीन काल से ही ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की भूमि माना जाता रहा है, आज एक नई दिशा में बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक, अर्थात् 2047 तक, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना हर नागरिक की आँखों में है। भारत सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएँ और नीतियाँ बनाई हैं, जिनका उद्देश्य एक समृद्ध, समावेशी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। भारत, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव, और विविधता से भरपूर सामाजिक संरचना के साथ, 2047 में अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने की ओर अग्रसर है। यह केवल एक ऐतिहासिक अवसर नहीं होगा, बल्कि एक नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। एक ऐसा भारत, जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो।

शब्द कुंजी— विकसित भारत 2047, सशक्त राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव।

Introduction

‘विकसित भारत 2047’ केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी विकास का प्रतीक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी प्रगति, सामाजिक समानता, पर्यावरणीय संतुलन, राजनीतिक स्थिरता, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मजबूती शामिल है। यह सपना तभी साकार होगा जब देश एक समग्र दृष्टिकोण अपनाए और सतत विकास को प्राथमिकता दे। विकसित भारत 2047 का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति से नहीं, बल्कि सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास से भी है। यह एक ऐसा भारत होगा जहाँ हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत अग्रणी होगा, बुनियादी ढाँचे का सशक्त विकास होगा, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। समावेशी विकास होगा, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा, अर्थात् आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भर भारत का नव निर्माण होगा।

भारत की अर्थव्यवस्था 2047 तक दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। इसके लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार आवश्यक होंगे—

1— विकसित भारत 2047: विनिर्माण और उद्योग का विस्तृत दृष्टिकोण— भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण और औद्योगिक विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार आवश्यक हैं।

भारत का वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य— भारत वर्तमान में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक इसे तीसरे स्थान पर पहुँचने की उम्मीद है। विनिर्माण क्षेत्र का भारत की GDP में योगदान लगभग 17% है, जिसे 2047 तक 25–30% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएँ लागू कर रही है। विकसित भारत 2047 के लिए मुख्य रणनीतियाँ

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत 2.0

स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा और आयात पर निर्भरता कम करना।

‘मेक इन इंडिया’ को एक वैश्विक ब्रांड बनाना और अधिक विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित करना।

सेक्टर—विशिष्ट प्रोत्साहन योजनाएँ, जैसे कि पीएलआई (Production Linked Incentive) योजना, जो भारत में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दी जा रही है।

औद्योगिक क्रांति 4.0 और डिजिटलीकरण—

इंडस्ट्री 4.0 में शामिल तकनीकों को अपनाना

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और ऑटोमेशन

3D प्रिंटिंग और नैनो-टेक्नोलॉजी

बिग डेटा और ब्लॉकचेन

स्मार्ट फैक्ट्रीज और रोबोटिक्स के माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाना।

क्लाउड—आधारित विनिर्माण प्रक्रियाएँ और डिजिटल सप्लाइ चैन का विकास।

हरित (ग्रीन) और सतत विकास उद्योग—

2030 तक भारत की कार्बन न्यूट्रलिटी नीति के तहत उद्योगों को ग्रीन तकनीकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।

सौर, पवन, और हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) ऊर्जा को अपनाना।

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना।

प्लास्टिक और अन्य हानिकारक सामग्रियों को हटाकर सस्टेनेबल मटेरियल्स का उपयोग।

बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक्स सुधार

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करना, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत (जो वर्तमान में भारत में GDP का 13–14% है) को घटाकर 8–9% तक लाया जाए।

रेलवे, एक्सप्रेसवे, और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विस्तार।

बड़े शहरों में विनिर्माण हब और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन SEZ को बढ़ावा।

विदेशी निवेश (FDI) और वैश्विक सहयोग

एफडीआई नियमों में सुधार करके विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करना।

भारत को वैश्विक सप्लाइ चैन का अभिन्न हिस्सा बनाना।

यूरोप, अमेरिका और अन्य विकसित देशों के साथ व्यापार समझौतों पर जोर देना।

'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' योजना को मजबूत करना, जिससे भारत के क्षेत्रीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान मिले।

मानव संसाधन और कौशल विकास

स्किल इंडिया मिशन के तहत विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम ताकि युवा मैनुफैक्चरिंग और उद्योग के लिए तैयार हो सकें।

तकनीकी शिक्षा में सुधार और इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों को इंडस्ट्री के अनुकूल बनाना।

AI और IoT पर आधारित नई स्किल ट्रेनिंग का विकास।

स्टार्टअप इंडिया और इनोवेशन हब को बढ़ावा देकर नवाचार को प्रेरित करना।

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य

क्षेत्र	वर्तमान स्थिति (2024)	लक्ष्य (2047)
विनिर्माण का GDP में योगदान	17%	25-30%
औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर	5-7%	10-12%
लॉजिस्टिक्स लागत (GDP का %)	13-14%	8-9%
निर्यात में वैश्विक रैंकिंग	टॉप 10	टॉप 5
रोजगार सृजन (मैनुफैक्चरिंग सेक्टर)	50 मिलियन	100 मिलियन+
इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन	2% (कुल वाहनों का)	50%+
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन	शुरुआती स्तर	विश्व में अग्रणी

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विनिर्माण और उद्योग को एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी। इसके लिए तकनीकी उन्नति, ग्रीन इनिशिएटिव्स, निवेश, स्किल डेवलपमेंट, और बुनियादी ढांचे में सुधार आवश्यक हैं। यदि ये सभी रणनीतियाँ सही ढंग से लागू होती हैं, तो भारत निश्चित रूप से वैश्विक औद्योगिक महाशक्ति बन सकता है।

2- विकसित भारत 2047 – कृषि सुधार- भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसमें नवाचार, प्रौद्योगिकी, और नीतिगत सुधारों के माध्यम से बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।

स्मार्ट और आधुनिक कृषि-

डिजिटल कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और बिग डेटा का उपयोग कर कृषि उत्पादन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

सटीक खेती (Precision Farming)— ड्रोन, सैटेलाइट मैपिंग, और सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर भूमि, जल और उर्वरकों का सही प्रबंधन।

जल और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग

माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम— ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देकर जल की बचत।

वाटर हार्वेस्टिंग— जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग कर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना।

जैविक और सतत कृषि

रसायन मुक्त खेती— जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों को बढ़ावा देना।

मल्टी-क्रॉपिंग और रोटेशन तकनीक— भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना।

किसान सशक्तिकरण और आय वृद्धि

किसान उत्पादक संगठन (FPOs)— किसानों को संगठित कर बाजार तक सीधी पहुंच देना।

कृषि स्टार्टअप्स और एग्री-टेक— नवाचार को बढ़ावा देकर किसानों के लिए नए अवसर पैदा करना।

MSP और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)— न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रभावी कार्यान्वयन और किसानों के खातों में सीधी सब्सिडी।

बुनियादी ढांचे का विकास

कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग— फसल खराब होने से बचाने के लिए आधुनिक भंडारण सुविधाएं।

ग्रामीण परिवहन नेटवर्क— खेतों से मंडियों तक बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था।

कृषि शिक्षा और अनुसंधान

कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों का विस्तार।

किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और डिजिटल साक्षरता अभियान।

विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए कृषि सुधारों को प्राथमिकता देनी होगी। आधुनिक तकनीकों, नीतिगत समर्थन और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर और टिकाऊ कृषि राष्ट्र बनाया जा सकता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैविक खेती और टेक्नोलॉजी आधारित कृषि प्रणाली से किसानों की आय दोगुनी होगी।

3-विकसित भारत 2047 और डिजिटल इंडिया— भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 का विजन प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य भारत को अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में डिजिटल इंडिया पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

डिजिटल इंडिया: विकसित भारत की नींव— डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। यह मिशन तीन मुख्य स्तंभों पर केंद्रित है।

- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
- डिजिटल सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच
- डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास

डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 के प्रमुख पहलू

- सभी नागरिकों को डिजिटल कनेक्टिविटी
- 5G और 6G नेटवर्क का विस्तार
- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्शन की पहुंच
- ब्रॉडबैंड सेवाओं का सार्वभौमिक कवरेज

ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाएं—

- डिजिटलीकरण से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी
- सभी सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता
- आधार, डिजिलॉकर, और उमंग जैसी सेवाओं का विस्तार

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेशन—

- सरकारी और निजी क्षेत्रों में AI और रोबोटिक्स का उपयोग
- डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से स्मार्ट निर्णय लेने की प्रणाली

डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम—

- डिजिटल पेमेंट का व्यापक उपयोग (UPI, RuPay, CBDC)
- स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों को बढ़ावा
- भारत को ग्लोबल इनोवेशन सेंटर बनाना

शिक्षा और स्वास्थ्य में डिजिटल परिवर्तन—

- ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म और डिजिटल क्लासरूम
- टेलीमेडिसिन और ई-हेल्थ सर्विसेज का विस्तार

डिजिटल इंडिया, विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाएगा। तकनीक के प्रभावी उपयोग से, भारत एक समावेशी, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बन सकता है। डिजिटल परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देगा।

4- विकसित भारत 2047: नवाचार और उद्यमिता— भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति में नवाचार (Innovation) और उद्यमिता (Entrepreneurship) की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बदलती वैश्विक परिस्थितियों, तकनीकी प्रगति, और स्टार्टअप संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत एक नवाचार-प्रेरित अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

नवाचार— भविष्य की नींव— नवाचार किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होता है। भारत में तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देकर नए समाधान विकसित किए जा रहे हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं।

प्रमुख नवाचार क्षेत्र—

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग – स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और उद्योगों में बड़े बदलाव ला रहे हैं।

ग्रीन टेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा – भारत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में विश्व में अग्रणी बनने की दिशा में है।

बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर – नई दवाओं, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों के विकास में नवाचार हो रहा है।

डिजिटल भारत और स्मार्ट तकनीक – डिजिटल भुगतान, ब्लॉकचेन और 5G जैसी तकनीकें भारत के विकास को गति प्रदान कर रही हैं।

उद्यमिता: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम— स्टार्टअप संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ावा देना भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है, जैसे—

स्टार्टअप इंडिया – नए स्टार्टअप्स को पंजीकरण में सरलता, कर में छूट और वित्तीय सहायता।

मेक इन इंडिया – विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को आगे बढ़ाना।

अटल इनोवेशन मिशन – नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना।

मुद्रा योजना – छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए आसान ऋण सुविधा।

भविष्य की संभावनाएँ और चुनौतियाँ—

- भारत को इनोवेशन हब बनाने की क्षमता।
- डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से विभिन्न उद्योगों में वृद्धि।
- वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की मजबूत भागीदारी।
- नवाचार के लिए उचित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता।
- स्टार्टअप्स को दीर्घकालिक समर्थन की जरूरत।
- स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता।

विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब नवाचार और उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। एक आत्मनिर्भर, नवाचार—आधारित और उद्यमशील भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि विश्व मंच पर एक अग्रणी शक्ति के रूप में उभरेगा। नवाचार और उद्यमिता भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे! भारत स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में एक वैश्विक हब बनेगा।

शिक्षा और कौशल विकास— विकसित भारत के लिए एक कुशल कार्यबल आवश्यक होगा।

- नई शिक्षा नीति (NEP 2020) का कार्यान्वयन शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाएगा।
- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास से युवा अधिक रोजगार योग्य बनेंगे।
- डिजिटल शिक्षा से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छात्रों के बीच की खाई कम होगी।

विज्ञान और तकनीकी प्रगति— 2047 तक भारत को एक वैज्ञानिक महाशक्ति बनाने के लिए—

- अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत को और आगे बढ़ाना होगा।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में निवेश बढ़ाना होगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग करना होगा।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास— पर्यावरण संतुलन बनाए रखना किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए आवश्यक है।

- ग्रीन एनर्जी और सतत विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा।
- वनों की कटाई पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाएगा।

सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण— 2047 का भारत एक समान अवसर वाला समाज होगा—

- महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर मिलेंगे।
- सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद और भेदभाव को समाप्त किया जाएगा।
- स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की पहुँच को बढ़ाया जाएगा।

2047 का भारत केवल आर्थिक और तकनीकी रूप से विकसित नहीं होगा, बल्कि यह एक समावेशी, पर्यावरण के अनुकूल और आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा। यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और देश के विकास में योगदान दे। एक नए भारत की ओर, विकसित भारत 2047 की ओर हमारा यह सफर निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा।

भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ—

1. **आर्थिक चुनौतियाँ—** भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन 2047 तक इसे एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई आर्थिक सुधारों की आवश्यकता होगी। औद्योगिकीकरण, स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल अर्थव्यवस्था, और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। साथ ही, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर भी ध्यान देना होगा।

2. **शिक्षा और कौशल विकास**— विकसित भारत की आधारशिला एक शिक्षित और कुशल जनसंख्या होगी। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार कर इसे व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी दक्षताओं से जोड़ना अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी रूप से लागू करना और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक होगा।
3. **स्वास्थ्य और चिकित्सा अवसंरचना** — कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में अभी भी कई खामियां हैं। 2047 तक भारत को एक सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा विकसित करना होगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध हों।
4. **तकनीकी उन्नति और नवाचार**— आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अनुसंधान, और डिजिटल परिवर्तन भारत के भविष्य को आकार देंगे। 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' को और अधिक प्रभावी बनाकर देश को वैश्विक नवाचार केंद्र में बदलना होगा।
5. **पर्यावरणीय चुनौतियाँ**— विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन बड़ी चुनौतियाँ हैं। 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'हरित ऊर्जा' को प्राथमिकता देकर भारत को टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा।

विकसित भारत 2047 की संभावनाएँ और समाधान—

1. अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाना— यदि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, तो उसे विनिर्माण, सेवा, और कृषि क्षेत्रों में नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। डैडम सेक्टर को मजबूत कर, उद्यमिता को बढ़ावा देकर और विदेशी निवेश आकर्षित कर आर्थिक विकास को तेज किया जा सकता है।
2. "शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा— भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाया जाना चाहिए। साथ ही, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित (STEM) शिक्षा को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा।
3. सशक्त स्वास्थ्य प्रणाली— टेलीमेडिसिन, आयुष्मान भारत योजना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य के डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता देकर एक सशक्त और समावेशी स्वास्थ्य तंत्र विकसित किया जा सकता है।
4. "वैश्विक नेतृत्व में भारत की भूमिका"— भारत को 2047 तक एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के लिए अपनी कूटनीति, रक्षा, और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना होगा।
5. "ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण" — सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देकर, जल संरक्षण को प्राथमिकता देकर, और सतत शहरीकरण को अपनाकर भारत स्वच्छ और हरा-भरा भविष्य सुनिश्चित कर सकता है।

2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना केवल एक सपना नहीं है, बल्कि यह एक यथार्थ बन सकता है यदि हम संगठित प्रयास करें। सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, और नागरिकों को मिलकर कार्य करना होगा ताकि यह लक्ष्य साकार हो सके। चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन संभावनाएँ भी अपार हैं। यदि सही दिशा में कदम बढ़ाए जाँ, तो भारत निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, और वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है।

संदर्भ सूची—**1. सरकारी दस्तावेज एवं रिपोर्ट्स—**

भारत सरकार का विकसित भारत 2047 दृष्टि पत्र

नीति आयोग की भारत/100 रिपोर्ट

आर्थिक सर्वेक्षण (वर्षवार)

पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट

आत्मनिर्भर भारत अभियान दस्तावेज

2. अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स एवं इंडेक्स—

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs) रिपोर्ट

विश्व बैंक की Ease of Doing Business रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की भारत संबंधी रिपोर्ट

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स

3. नीति एवं कानून—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020)

डिजिटलीकरण और डिजिटल इंडिया नीति

स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया पहल

बुनियादी ढांचा एवं शहरी विकास नीति

4. प्रमुख सेक्टर—विशिष्ट नीतियां—

कृषि एवं ग्रामीण विकास रिपोर्ट

नवीकरणीय ऊर्जा मिशन एवं पर्यावरणीय नीति

स्वास्थ्य एवं आयुष्मान भारत योजना

औद्योगिक और व्यापारिक नीतियां

5. विशेषज्ञ लेख एवं अकादमिक शोध—

आईआईटी, आईआईएम और प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित शोध पत्र

आर्थिक एवं सामाजिक नीति संस्थानों की रिपोर्ट्स

प्रमुख समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित विशेषज्ञों के लेख

6. डिजिटल स्रोत एवं डेटा पोर्टल्स—

MyGov और नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइटें

RBI, SEBI और अन्य नियामक संस्थाओं की रिपोर्ट्स

7. Books

- **India 2020: A Vision for the New Millennium**

पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और वाई.एस. राजन द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत के विकास के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जो 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक कदमों पर केंद्रित है।

- **The India Way: Strategies for an Uncertain World**

एस. जयशंकर द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत की विदेश नीति और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका पर विचार करती है, जो 2047 तक भारत के विकास के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

- **Reimagining India: Unlocking the Potential of Asia's Next Superpower**
मैकिंजी एंड कंपनी द्वारा संपादित इस पुस्तक में विभिन्न विशेषज्ञों के निबंध शामिल हैं, जो भारत की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं।
- **India Unbound**
गुरचरण दास द्वारा लिखित यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और उसके प्रभावों पर केंद्रित है, जो भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- **The Rise of India: Its Transformation from Poverty to Prosperity**
ब्रह्मा चेलानी द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन पर केंद्रित है, जो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण है।